# यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
**केन्द्रीय कार्यालय** : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
**पत्र व्यवहार** : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**


**परिपत्र संख्या** : 2019–22/35/2020 **दिनांक** : 12.03.2020

**सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों**
**जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु**

प्रिय साथियों,

## 10 बैंकों के प्रस्तावित विलय तथा आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के विरोध में 27 मार्च, 2020 को अखिल भारतीय हड़ताल

उपरोक्त विषय में हमारे पूर्व परिपत्र संख्या 2019–22/31/2020 दिनांक 05.03.2020 का संज्ञान लें जिसके माध्यम से एआईबीईए–एआईबीओए द्वारा संयुक्त रूप से जारी आंदोलनात्मक कार्यक्रमों तथा हड़ताल के आह्वान के विषय में अवगत कराया गया था। अब एआईबीईए केन्द्रीय कार्यालय द्वारा 27 मार्च, 2020 की हड़ताल के संबंध में परिपत्र संख्या 28/180/2020/18 दिनांक 12.3.2020 जारी किया गया है जिसका अनूदित सार सभी इकाईओं एवं सदस्यों की सूचना, संज्ञान एवं अनुपालन हेतु नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

**(मदन मोहन राय)**
**महामंत्री**

---

प्रिय साथियों,

- **10 बैंकों के प्रस्तावित विलय तथा आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के विरूद्ध 27 मार्च, 2020 को हमारी अखिल भारतीय हड़ताल की सफलता के लिए पूरी तैयारियां करें**

अब तक हमारी सभी इकाईओं को 10 बैंकों के प्रस्तावित विलय के विरूद्ध और आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के विरूद्ध तथा अन्य संबंधित मांगों को लेकर विरोध करने के लिए 27 मार्च, 2020 को अखिल भारतीय हड़ताल के आह्वान के संबंध में एआईबीईए एवं एआईबीओए से हमारा संयुक्त परिपत्र प्राप्त हो गया होगा। हमें यकीन है कि हमारी सभी इकाईयां इस हड़ताल की सफलता की तैयारियां कर रही हैं। 26.2.2020 को चैन्नई में हुई हमारे एआईबीईए पदाधिकारियों की बैठक के निर्णय के अनुसार, हमने सरकार के इन अवांछित कदमों के विरूद्ध संभावित संयुक्त कार्यक्रम के लिए यूएफबीयू के तहत अन्य यूनियनों के साथ मामले को उठाया। चूंकि इस संबंध में कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, इसलिए हमने 27.3.2020 को हड़ताल का आह्वान किया है।

**हमें बैंकों के विलय का विरोध करने की जरूरत है** : हम इस बात से अवगत हैं कि सरकार विलय योजना के साथ आगे बढ़ रही है जब से इसे मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति मिली है और एकीकरण की योजना को स्वीकृति मिली है। हालांकि, सरकार का इस तरह का प्रमुख प्रतिगामी कदम निर्विरोध नहीं चल सकता। समय साबित करेगा कि बैंकों के विलय के लिए एआईबीईए का विरोध सही था जैसे एआईबीईए के कई अन्य दृष्टिकोण जो आज बैंकिंग क्षेत्र में हो रहा है उससे सही सिद्ध हो रहे हैं। नए निजी बैंकों को दिए जा रहे बढ़ावे के विरूद्ध हमारा संघर्ष यस बैंक के पतन से पूरी तरह सही सिद्ध हो गया है। इसलिए हमें बैंकों के इस थोक विलय का विरोध एवं प्रतिरोध करने की जरूरत है।

*जारी पृष्ठ 2*

**हमें आईडीबीआई बैंक के निजीकरण का विरोध करने की आवश्यकता है** : इसी तरह, जबकि निजी क्षेत्र बैंकिंग कई नए निजी बैंकों में चल रही गतिविधियों और यस बैंक जिसका अत्यधिक ढ़िढोरा पीटा गया, के पतन के कारण गंभीर तनाव के तहत है, यह एक विडंबना है कि हाल के बजट में, सरकार ने घोषणा की है कि आईडीबीआई बैंक में उनकी पूरी 47% हिस्सेदारी निजी हाथों में दी जायेगी और इस तरह आईडीबीआई बैंक के करीब–करीब निजीकरण की घोषणा की है। आईडीबीआई बैक द्वारा सामना की जाने वाली विशाल एनपीए की समस्या केवल निजी कंपनियों और कॉर्पोरेट्स के विशाल ऋणों की चूक है और फिर भी सरकार आईडीबीआई बैंक को उसी दुष्ट निजी क्षेत्र को सौंपना चाहती है।

**यस बैंक का पतन – क्या सरकार और आरबीआई खुद को निरपराध ठहरा सकते हैं ?** स्पष्ट संकेतों के बावजूद, सरकार और आरबीआई – यस बैंक में जो चल रहा था उसके बारे में – शायद, अकारण और जानबूझकर – मूक दर्शक बने रहे। अब एक के बाद एक चीजें सामने आ रही हैं। जब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अधिक पूंजी के लिए अनुरोध कर रहे थे, तो सरकार ने कहा कि हम कर–दाताओं के धन से नहीं खेल सकते, लेकिन जब यस बैंक की बात आई, तो एसबीआई के माध्यम से उन्हें बेलआउट करने की बहुत जल्दी है। हम राणा कपूर और यस बैंक के अन्य सभी शीर्ष अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए, यस बैंक संकट पर समय से कार्रवाई करने की आरबीआई की ओर से घोर लापरवाही और निष्क्रियता पर, तथा उभरते बैंकिंग संकट से निपटने में सरकार की अक्षमता पर अभियान चलायेंगे।

**हम खराब ऋणों की वसूली चाहते हैं – सरकार समाधान और सजावटी छंटनी की बात करती है** : खराब ऋणों का संचित होना आज बैंकों के सामने मुख्य और गंभीर मुद्दा है। एआईबीईए की ओर से हम बड़े कॉर्पोरेट चूककर्ताओं पर कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एआईबीईए द्वारा काफी संघर्ष और अभियान चलाने के बाद, हमें प्रसन्नता है कि आरबीआई अब इस बात पर सहमत हो गया है कि कुछ शीर्ष चूककर्ताओं के नाम प्रकाशित किये जायेंगे। हमें खराब ऋणों के खिलाफ अपने संघर्ष को जारी रखने और सघन करने की आवश्यकता है। जब तक खराब ऋणों की वसूली नहीं हो जाती, तब तक हमारे बैंकों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यवश, वर्तमान सरकार 'ऋणों के समाधान' का आग्रह कर रही है जिसके परिणामस्वरूप भारी सजावटी छंटनी होती है। इन सजावटी छंटनियों के कारण, बैंकों को धन की हानि और नुकसान हो रहा है। इसलिए खराब ऋणों की वसूली के लिए हमारे संघर्ष को भी बढ़ाने की जरूरत है।

इस पृष्ठभूमि में, 27 मार्च, 2020 को हमारी हड़ताल महत्वपूर्ण है। हड़ताल के महत्व को समझाने और हड़ताल की पूर्ण सफलता के लिए हमारे सदस्यों को तैयार करने के लिए सभी केन्द्रों पर बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।

हम अपनी हड़ताल को भ्रात्रिय समर्थन देने के लिए अन्य सभी यूनियनों से संपर्क कर रहे हैं।

आईये चलें, आगे बढ़ें, हड़ताल को सफल बनायें।

**बैंकों के अवांछित विलय का नाश हो।**
**आईडीबीआई बैंक के निजीकरण का नाश हो।**

अभिवादन सहित,

आपका साथी,
ह0..
**सी.एच. वेंकटचलम्**
**महामंत्री**